Lack of Maintenance facilities in Government Quarters

2876. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that paints have not been sprayed on electrical fittings in various Government quarters in Delhi, especially in Laxmi Bai Nagar;

(b) whether it is a fact that a large number of complaints are pouring in for welding-related works but there is no arrangements of its own, with the CPWD; and

(c) if answer for (a) and (b) be in the positive, what steps are being taken to solve those problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (a) Electrical light fittings are not painted by CPWD either by spray painting or hand painting. Only ceiling fans are periodically painted once in every 4-5 years by CPWD for proper upkeep of the ceiling fans. The ceiling fans in Laxmi Bai Nagar were last painted during 92-93.

(b) No Sir, the complaints relating to welding have been very occasional and are being attended to as and when received, through contractor.

(c) In view of reply to (a) & (b) above, the question does not arise.

आगरा के लिए ताज ट्रैपेज़ियम योजना

2877. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से आगरा की पेयजल और मल जल प्रणाली के लिए एक ताज ट्रैपेज़ियम योजना मंजूर की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना का 50% व्यय केन्द्र सरकार को वहन करना था;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को चार वर्षों में 114.10 करोड़ रुपये, वर्ष 1997-98 और वर्ष 1998-99 में क्रमशः 31.68 करोड़ रुपये और 41.8 करोड़ रुपये अदा करने थे;

(घ) अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे पर्यावरण व वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि ताज संरक्षण मिशन की मंजूरी योजना आयोग से मिल चुकी है तथा इस स्कीम का वित्तपोषण, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बराबरी का अंश देकर किया जाना है ताकि गोकुल और आगरा बैरेज का निर्माण तथा आगरा सिटी में जल निकासी प्रणाली तथा सफाई व्यवस्था के सुधार सहित स्कीम के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन हो सके।

(ग) से (ङ) पर्यावरण व वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अभी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसलिए आगरा की पेयजल तथा मल-जल प्रणाली की स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार ने कोई धन उपलब्ध नहीं कराया है।

Encoroachment on Public Land

2878. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether encroachments on public lands are assuming alarming proportions with the mushrooming vendors on both sides of roads in Delhi with the connivance of the DDA and Corporation staff and officials of the law enforcing agencies;

(b) if so, whether the only way to stop such encroachments is to hold the SHOs responsible for it in their respective areas; and

(c) the steps taken in this direction?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) to (c) No, Sir. As and when such encroachment is detected on reported, action is taken by the concerned authorities under the relevant laws.

Delhi Police have reported that all the Assistant Commissioners of Police/ S.H.Os. have been directed to keep their staff alert and take stern action against the encroachers and also inform the concerned land owning agency about any encroachments for their removal.

Printing of Money Order Forms

2879. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the pending orders of the Directorate of Printing for Money Order forms and A.D. cards etc. pertaining to the Department of Posts as on 31st March, 1998 lying with various Government Presses; and

(b) the reasons for delay in printing?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) The orders for Money Order Forms (M O - 8) and A.D. Cards (R P - 54) pertaining to the Department of Posts as on 31.3.98 pending in the Government of India Presses are 26,14,720 pads and 3,64,96,000 respectively.

(b) The reasons for delay in printing of Money Order Forms and A.D. Cards are as follows:—

(i) Annual production capacity of the Presses is getting reduced every year due to natural wear and tear.

(ii) Short & erratic supply of electricity by the State Electricity Boards results in idling of machines.

(iii) The Presses also undertake printing jobs of other Ministries/Departments on priority basis. Due to change in priority of the printing jobs, all works cannot be completed strictly on first come first serve basis.

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में जनसंख्या

2880. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए आये दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ दिया जाता है;

(ग) इन झुग्गी-झोपड़ियों में कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) इन झुग्गी-झोपड़ियों में इलाज तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग ने बताया है कि 1994 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार 20 लाख से अधिक लोग 1080 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में रह रहे थे।

(ख) और (ग) फिलहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग के माध्यम से निम्नलिखित त्रिआयामी योजना चलाई जा रही है:—

(i) सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए तत्काल अपेक्षित भूमि से पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों (जो जनवरी, 1990 को विद्यमान थे) का पुनः स्थान निर्धारण/पुनर्वास;

(ii) ऐसी सार्वजनिक भूमि, जो सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए रखी गई है किन्तु कार्यान्वयन के लिए उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, पर स्थित झुग्गी-झोपड़ी समूहों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना;

(iii) सार्वजनिक भूमि जो किसी परियोजना के लिए नहीं रखी गई है तथा जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, उस भूमि पर स्थित झुग्गी-झोपड़ी समूहों का भूस्वामी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद उसी स्थान पर उन्नयन।